अफोर्डेबल स्कूलिंग
कमेंडेबल लर्निंग

NISA
National Independent Schools Alliance

namaskar

खंड १ | भाग २ | मार्च-अप्रैल २०१४ | English Adaptation
नीसा परिवार की ओर से

१९ राज्य
८०००+ स्कूल
१६,००,०००+ शिक्षार्थी
आज ही **सदस्य बनिए**! नीसा से जुड़िये

नेशनल इन्डिपेन्डेन्ट स्कूल्स एलायंस (नीसा) भारत के उन सभी अफोर्डेबल प्राईवेट स्कूलों (एपीएस) की एकीकृत आवाज़ है, जो आर्थिक तौर पर गरीब लोगों तक सस्ती और गुणता-पूर्ण शिक्षा पहुँचाने के संयुक्त उद्देश्य से जुड़े हुए हैं!

सम्पादकीय: अकेले नहीं हैं हम

कम लागत वाली अच्छी शिक्षा एक वैश्विक संकल्पना है: जहाँ भी गुणतापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा देने में सरकारें असफल रही हैं, वहाँ मंहगी निजी शिक्षा और कम स्तर की सरकारी शिक्षा के अंतर को पूरा करने के लिए बजट प्राइवेट स्कूल (बीपीएस) आगे आये हैं. जानिए दुनिया की तीन और ऐसी संस्थाओं को, जो **नीसा** की तरह ही इन स्कूलों को बचाती और बढ़ाती हैं.

इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ़ साउथ अफ्रीका (आईसैसा) दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र के स्वतंत्र स्कूलों की सबसे बड़ी और पुरानी संस्था है, जिसके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, स्वाज़ीलैंड, नैमीबिया व अंगोला के ७०० से अधिक स्कूल हैं. ये सदस्य स्कूल १२,५०० से अधिक शिक्षकों के ज़रिये १५४,००० से अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं. अधिक जानिए: www.isasa.org.

केन्या इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन (कीसा) तक़रीबन १००० स्वतंत्र सामुदायिक स्कूलों की संस्था है, जो केन्या की अनौपचारिक बस्तियों में पाए जाने वाले कम आमद वाले घरों में बच्चों को शिक्षा देते हैं.
अधिक जानिए: www.schoolskenya.net/index.php/Kenya-Independent-Schools-Association-KISA.html.

नाइजीरिया की **एसोसिएशन ऑफ़ फोर्मिडेबल एजुकेशन डेवलपमेंट** (एफेड), जिसके अंतर्गत सरकारी मान्यताप्राप्त और ग़ैर मान्यताप्राप्त बढ़ते हुए स्कूल आते हैं, गरीब परिवारों को अच्छी और सस्ती शिक्षा प्रदान करती है. यह लोकतंत्रीय संस्था एक ओपन डोर पॉलिसी का अनुसरण करती है, और नाइजीरिया की फ़ेडरल व राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है. अधिक जानिए: www.afed.info.

इवेंट्स

सभा | 25 अप्रैल २०१४, नई दिल्ली

धारा १२ (१) (सी) पर राज्यव्यापी सम्मलेन

इंडस एक्शन और सेंट्रल स्कुअर फाउंडेशन ने राइट टू एजुकेशन (आरटीई) एक्ट की धारा १२ (जो ग़ैर-सहायताप्राप्त निजी स्कूलों में कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों को दाखिले में २५% आरक्षण का प्रावधान देती है) को लागू करने के ढंग पर विचार करने के लिए सम्मलेन रखा. बच्चों के सहज सामाजिक-शैक्षिक समावेश को सुनिश्चित करने के तरीके खोजने के लिए विशेषज्ञों के दो पैनलों ने इस अनुच्छेद पर चर्चा की. अधिक जानिए: http://righttoeducation.in/project-eklavya-campaign-10-report

शिखर सम्मलेन | १९-२० अप्रैल २०१४, नई दिल्ली

नीसा राष्ट्र-स्तरीय बैठक (नेशनल लेवल मीटिंग)

अलायन्स का मैंडेट तय करने और २०१४-१५ की वार्षिक परियोजना बनाने के लिए नीसा ने अपनी पहली राष्ट्र स्तर की बैठक की. १४ राज्यों और नीसा टीम की ओर से ५०+ प्रतिनिधिओं ने अपने क्षेत्रों में विकास का ब्यौरा दिया, और बजट प्राइवेट स्कूलों की गुणवत्ता, स्कूल -मान्यताप्राप्ति/बंद-होने के खतरों और पक्षपोषण से जुड़ी बातों पर विचार किया. नीसा मैंडेट भी तय किया गया.
अधिक जानिए: LINK.

फ़ीचर: द ब्यूटिफुल ट्री

प्रोफ़ जेम्स टूली की किताब 'द ब्यूटिफुल ट्री' भारत, अफ्रीका और चीन के सबसे ग़रीब तबकों में रहने वाले उन परिवारों और शिक्षकों की एक प्रेरणादायक यात्रा-वृतांत है, जिन्होंने असफल सार्वजनिक शिक्षा के ज़वाब में अपने खुद के निजी स्कूलों को बनाया और बढ़ाया है.
रोचक ढंग से लिखा गया यह वर्णन उन बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षा-उद्यमियों (एडू-प्रेनयूर्स) से टूली के साक्षात्कारों का लेखाजोखा है, जिनके अस्तित्व को सरकारें कट्टरता से अस्वीकारती रही हैं. उन्होंने टूली को सिखाया कि ग़रीब शिक्षा के नाम पर किसी रहम के भरोसे नहीं हैं–वे अपने खुद के स्कूल बना रहे हैं और खुद को बचाना सीख रहे हैं.

यह पुस्तक, जिसका शीर्षक महात्मा गाँधी की उपनिवेशवाद-पूर्व भारत को दी गई उक्ति से प्रेरित है, तृतीय विश्व में हुई गलतियों पर शोक व्यक्त करती एक और पुस्तक नहीं है. यह पुस्तक उन बातों के बारे में है जो कि सही हो रही हैं, और एक सरल सबक देती है: उद्यमशीलता की भावना, और बच्चों के प्रति अभिभावकों का प्यार — दोनों से मिलकर ही गरीबी के दमघोंटू असर पर काबू पाया जा सकता है.

जेम्स टूली नीसा के प्रमुख संरक्षक और विश्व भर में नीसा जैसी संस्थाओं के मित्र हैं.
अपनी 'द ब्यूटिफुल ट्री' प्रति के लिए लिखें: nisa@ccs.in

क़ानूनी सलाह लें: लीगल बाउंड्रीज़

प्र: आरटीई के अधीन क्या स्कूलों के क्षेत्रफ़ल/कक्षा के आकार को लेकर कोई निर्धारित मापदंड हैं? हरगोपाल शर्मा, पंजाब
उ: हाँ, आरटीई के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े परिभाषित मानदंड हैं. आप पंजाब शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रति आरटीई प्लेटफ़ॉर्म पर देख सकते हैं.
वह यहाँ उपलब्ध है: http://righttoeducation.in/states.

प्र: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (ऑटिज्म) के दाखिले के लिए क्या मानदंड हैं? क्या मुझे अभिभावकों से कुछ विशेष दस्तावेज़ लेने होंगे? कविता मारवाह, उत्तर प्रदेश
उ: CWSN को पर्सन्स विद दिसेबिलिटीज़ एक्ट १९९५ में दिए गए अनुच्छेद २ (टी) को पूरा करना होगा, और इस संदर्भ में एक प्रमाणपत्र देना होगा. स्कूल/स्थानीय प्राधिकारी को CWSN के लिए यातायात मुहैया कराना होगा. उत्तर प्रदेश राज्य में उन्हें मुफ्त विशेष शिक्षा और शिक्षा- सामग्री देने का भी प्रावधान है.

प्र: अगर स्कूल को फीस का सरकारी हिस्से का मुआवज़ा नहीं मिला है, तो स्कूल प्रबंधन को क्या करना चाहिए? टी बसावराज, कर्णाटक
उ: आपको सीधा कर्णाटक सरकार के शिक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए. आप आरटीई प्लेटफ़ॉर्म पर एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज़ कर सकते हैं.

आर टी ई से जुड़ा कोई सवाल है? हमसे पूछिए!
अधिक जानिए: www.rightoeducation.in.

लीगल बाउंडरीज़ आपकी आरटीई और निजी स्कूलों से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर है, चाहें आप स्कूल एडमिनिसट्रेटर, ओनर या अभिभावक हों .

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी आरटीई से जुड़े मसलों पर **मुफ्त क़ानूनी सलाह और राय** देता है. हम कानूनी विशेषज्ञ और आईजस्टिस अधिवक्ता **प्रशांत नारंग** से सलाह मशवरा लेते हैं.

अपने प्रश्न prashant@ijustice.in पर भेजें. अपनी बात साफ़ और संक्षिप्त रखें और शीर्षक में: 'लीगल बाउंडरीज़ - नीसा प्रश्न' लिखें:

**आरटीई से जुड़े क़ानूनी सवाल हैं?
मुफ्त सलाह और राय लें!**

अभिमत: नीसा मैंडेट

गत अप्रैल १९-२० को नई दिल्ली में हुई नीसा की वर्ष की प्रथम राष्ट्र-स्तरीय बैठक का उद्देश्य, अन्य मुद्दों के अलावा, नीसा मैंडेट — उन चीज़ों की सूची जो नीसा को परिभाषित करती हैं, और बताती हैं कि नीसा क्या मानती और करती है (और क्या नहीं) — को तय करना था. कार्य समूहों के माध्यम से बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए आवश्यकता-आकलन करके नीसा की (हर प्रदेश के दो सदस्यों से प्रतिनिधित) एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अलायन्स की प्राथमिकताओं को सामने रखा. समूहों ने फिर अपने मुद्दों पर काउंसिल के और सदस्यों से चर्चा कर तालमेल बिठाया. समूह प्रतिनिधिओं द्वारा प्रस्तुत किये गए जो मुख्य मुद्दे उभर कर आये, वे हम आपसे साझा कर रहे हैं:

"जहाँ स्कूल फ़ीस और शिक्षकों के वेतन की बात आती है, तो हमें अपने खुद के नियम बनाने देने चाहिए; हम वेतन को स्कूल फीस से जोड़ भी सकते हैं. हमारे स्कूलों को कमर्शिअल दरों से जबरन बिजली, पानी, गैस और अन्य सुविधाएँ खरीदने से छूट मिलनी चाहिए. शिक्षकों की योग्यता/प्रशिक्षण, फंडिंग और मान्यताप्राप्ति के मानदंडों से जुड़े मुद्दे नीसा मैंडेट में हों."

"हमारे स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हमारे मैंडेट का एक अहम् हिस्सा होना चाहिए–हमें नेतृत्व प्रशिक्षण, अच्छे मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण और रिटेंशन, और बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए एक मज़बूत सहयोग तंत्र में निवेश करना चाहिए.इसके अलावा, नीसा मैंडेट में हमारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक निश्चित न्यूनतम दर्जे के विकास पर ज़ोर देना चाहिए."

"फाइनेंस, मान्यताप्राप्ति और शिक्षक/प्रबंधन प्रशिक्षण से जुड़े हुए मुद्दे शीर्ष प्राथमिकता पर हैं. फिर, हमारे स्कूलों और अन्य निजी/सरकारी स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों के साथ समान बर्ताव सुनिश्चित करने पर भी हमें ज़ोर देना चाहिए. हम नीसा के लिए एक समग्र पाठ्यचर्या विकसित करने के बारे में भी सोच सकते हैं."

आर सी जैन
प्रेजिडेंट, नीसा

एकता सोधा
वाईस प्रेजिडेंट—क्वालिटी, नीसा

कुलभूषण शर्मा
वाईस प्रेजिडेंट—एडवोकेसी , नीसा

नीसा कार्य पर: स्टर इनोवेशन

सम्पूर्ण स्कूल सुधार की तरफ नीसा स्टर एजुकेशन के साथ मिलकर काम करती है. यह साझेदारी, माइक्रो-इनोवेशन, जो शिक्षा के कुछ विशिष्ट पहलुओं को शामिल करते हुई विशेष रूप से तैयार किये गए कार्यकलाप हैं, के माध्यम से कार्य करती है. ऐसी ही एक माइक्रो-इनोवेशन का नाम **अभिभावकों के साथ काम** है:

जनता मॉडर्न पब्लिक स्कूल पूर्वी दिल्ली के विजय पार्क में है, जो कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ मुख्यतया बेहद कम पढ़े-लिखे, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग रहते हैं.

स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षा-उद्यमी, एच के शर्मा, काफी समय से जागरूक और सचेत अभिभावकों की एक ऐसी फौज़ खड़ी करने में लगे हैं, जो अपने बच्चों को पड़ोस के स्कूलों में भेजना चाहते हैं. फिर भी, शर्मा कुछ समय से देख रहे हैं कि खुद पढ़े-लिखे न होने के चलते बहुत से अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने में हमेशा या तो बिलकुल ही नहीं जुड़ते, या फिर प्रभावशाली तरीके से कुछ योगदान नहीं दे पाते.

अभिभावक और समुदाय संलग्न विषय के तले *अभिभावकों के साथ काम* शीर्षक से माइक्रो-इनोवेशन को, नीसा ने माँ-बाप की बच्चों की शिक्षा में भागीदारी को मापने और बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया. शर्मा ने बच्चों से उनके घर पर मिलने वाले सहयोग के स्तर को एक प्रश्नमाला के ज़रिये मापने की कोशिश की, और उनसे 'आपके साथ कौन और कितनी देर टीवी देखता है', 'क्या आपने घर-परिवार में कभी लड़ाई होते देखी है', 'आपके माँ-बाप क्या करते हैं' आदि प्रश्न पूछे. फिर, उन्होंने इकट्ठा की गयी जानकारी को मिलाकर उसका आकलन किया.

शर्मा ने अभिभावकों के साथ मुलाकात की और उनसे पूछा कि वे अपने बच्चों को कुछ साल बाद कैसा देखना चाहते हैं; फिर, इकट्ठा की गयी जानकारी को उनके साथ साझा किया. माँ-बाप बच्चों को कैसे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और बच्चे इसे खुद कैसे देखते हैं — अभिभावकों द्वारा इस अंतर को एहसास करते देखना रोचक था. शर्मा ने शिक्षा को देखने के नज़रिए को बदलने और घर-परिवार में एक सकारात्मक, सहायक वातावरण को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दिया.

अभिभावकों के साथ काम एक रोचक माइक्रो-इनोवेशन बनकर सामने आई. उसने अभिभावकों और शिक्षकों को सालभर मिलकर काम करने की ज़रुरत को पहचान दिलाई.

शर्मा बताते हैं कि माँ-बाप अब घर पर अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी मदद मिल रही है. साथ ही, समय के चलते, स्कूल और अभिभावकों के बीच विश्वास और भी पक्का हो गया है.

स्टर माइक्रो-इनोवेशन्स के बारे में और पढ़ें:
http://www.stireducation.org/sites/ default/files/ STIR_India_2012-14_Micro- Innovations_4.pdf.

RTE NEWS

टाइम्स ऑफ़ इंडिया | ११ मई २०१४
Toilet, water must in schools: Supreme Court
www.timesofindia.indiatimes.com/India/Toilet-water-must-in-schools-Supreme-Court/articleshow/34945462.cms

टाइम्स ऑफ़ इंडिया | ७ मई २०१४
HC relief to Haryana private schools
www.timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/HC-relief-to-Haryana-private-schools/articleshow/34748097.cms

द गार्जियन | ७ मई २०१४
How technology is set to transform India's fragmented education system
www.theguardian.com/technology/2014/may/07/technology-transform-india-education-system

टाइम्स ऑफ़ इंडिया | ७ मई २०१४
State can't impose mother tongue in private schools: SC
www.timesofindia.indiatimes.com/india/State-cant-impose-mother-tongue-in-private-primary-schools-SC/articleshow/34750820.cms

बार एंड बेंच | ६ मई २०१४
Supreme Court holds minority schools to be exempt from RTE Act (download judgment)
www.barandbench.com/content/212/constitutional-validity-article-155-and-rte-act-battery#.U3BkdoGSx_U

Courtesy: RightToEducation.in

NISA
National Independent Schools Alliance
ए ६९, हौज़ ख़ास, नयी दिल्ली ११००१६ भारत | +९१ ११ २६५३७४५६, ९८९९४८५६६७, ८१३०५६२७०२
www.nisaindia.org | nisa@ccs.in सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की एक पहल
/RightToEducation
theRTEplatform
/company/Centre-for-Civil-Society
/theRTEplatform
SpontaneousOrder.in